गर्मी की मार से दूध हुआ महंगा, घटा उत्पादन

बड़वानी, (नवभारत)। भीषण गर्मी का असर अब दूध उत्पादन पर साफ दिखाई देने लगा है। जिले में दूध का उत्पादन घटने से इसके दामों में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो गई है। शहर में भैंस का दूध 66 से 70 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है, जबकि गाय का दूध 65 तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।

पशुपालकों के अनुसार गर्मी बढ़ने से मवेशियों का दूध उत्पादन कम हो जाता है। पानी की कमी व बढ़ते तापमान की वजह से पशुओं की क्षमता प्रभावित होती है। पहले जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन करीब 50 टन दूध का उत्पादन होता था, जो अब घटकर लगभग 42 टन रह गया है।

फैक्ट फाईल

- जिले में 10 लाख से अधिक दुधारू पशु
- प्रतिदिन 50 टन तक दूध उत्पादन
- उत्पादन में 8 टन तक की गिरावट
- दूध के दाम 5 से 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े
- शहर में दूध 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा

दूध व्यापारियों का कहना है कि जून माह में उत्पादन और कम होने की संभावना है। गांवों में भैंस का दूध 50 से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर और गाय का दूध 45 से बढ़कर 55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर शहर की दूध आपूर्ति पर पड़ा है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले एक माह में दूध के दाम लगातार बढ़े हैं, जिससे कई परिवारों ने दूध की खपत में कटौती शुरू कर दी है।

कुछ समय पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई की वजह से कई कारोबारियों ने गांवों से दूध उठाना कम कर दिया था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के दाम गिर गए थे। कई स्थानों पर पशुपालकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। अब कार्रवाई धीमी पड़ने के बाद दूध का उठाव बढ़ा है और दामों में फिर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक वर्ष में दूध के भाव करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं।

पिछले वर्ष सर्दियों के दौरान दूध के भाव अपेक्षाकृत कम रहे थे। भैंस का दूध करीब 50 रुपए और गाय का दूध 40 से 45 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा था। अक्टूबर में कुछ समय के लिए दाम बढ़े, लेकिन नवंबर में फिर गिरावट आ गई। इस बार गर्मी शुरू होते ही दूध पर महंगाई की मार दिखाई देने लगी है। व्यापारियों का मानना है कि उत्पादन में गिरावट के कारण आने वाले हफ्तों में कीमतों पर और दबाव बन सकता है।

पशुपालक कैलाश धनगर का कहना है कि दूध ही उनकी आय का मुख्य स्त्रोत है, लेकिन गर्मी बढ़ने से पशु कम दूध दे रहे हैं। उपभोक्ता यश शर्मा ने बताया कि पिछले एक माह में दूध के भाव करीब 6 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। मोहल्लों में 66 से 70 रुपए प्रति लीटर तक दूध बिक रहा है, घरेलू खर्च प्रभावित हो रहा है।

> **जुलाई से मिल सकती है राहत**
>
> पहले गांवों से प्रतिदिन करीब 29 हजार लीटर दूध आता था, जो अब घटकर 23 हजार लीटर रह गया है। गर्मी की वजह से उत्पादन कम हुआ है और जून में इसमें और गिरावट आ सकती है। हालांकि जुलाई से मौसम में सुधार के साथ दूध की उपलब्धता बढ़ने और कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।
>
> कुंता चौहान, प्रभारी
> सांची दुग्ध संघ बड़वानी

मानदेय निकालने के लिए मांगी थी 20 हजार की रिश्वत

नव भारत न्यूज

इंदौर/बड़वानी. आंगनवाड़ी सहायिका का 8 माह का रुका मानदेय निकालने के लिए 20 हजार रुपए रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपए लेते एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया.

मामला महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना ठीकरी (जिला बड़वानी) का है. संगोदा बैडीपुरा निवासी आवेदिका की नियुक्ति 17 सितंबर 2025 को आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर हुई थी, लेकिन उसे अब तक मानदेय नहीं मिला था. शिकायत के अनुसार परियोजना अधिकारी और भृत्य ने मिलीभगत कर मानदेय निकालने के बदले 20 हजार रुपए की मांग की. आवेदिका ने इसकी शिकायत लोकायुक्त इंदौर से की. सत्यापन में मामला सही पाए जाने पर मंगलवार को ट्रैप दल गठित किया, कार्रवाई के दौरान भृत्य के कहने पर एक दलाल ने आवेदिका से 5 हजार रुपए लिए, जिसे टीम ने मौके पर ही पकड़ लिया. मामले में परियोजना अधिकारी, भृत्य और दलाल तीनों की भूमिका सामने आई है. लोकायुक्त ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक, राजेश सहाय ने बताया कि आंगनवाड़ी सहायिका से मानदेय के बदले 20 हजार रिश्वत मांगने का मामला है. लोकायुक्त ने ट्रैप कर 5 हजार लेते आरोपी पकड़ा, तीनों की भूमिका जांच में है .

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर माफी की मांग

- राज्यपाल के नाम तहसीलदार को
- सौंपा ज्ञापन

सेंधवा, (नवभारत)। ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध किया। मंगलवार दोपहर 12.30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

उनका आरोप है कि इस टिप्पणी से किसानों सहित आम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया कि जीतू पटवारी किसान परिवार से आते हैं और उनके खिलाफ की गई टिप्पणी से कृषक वर्ग में भी असंतोष है।

लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन की मांग

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर संविधान की शपथ के अनुरूप आचरण नहीं करने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री की टिप्पणी की निंदा करते हुए मामले की जांच कराने और उन्हें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने की हिदायत देने की मांग की गई। साथ ही भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित भाषा के प्रयोग से बचने के निर्देश जारी करने की मांग भी रखी गई। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गाडवे ने बताया कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण एवं मर्यादित तरीके से अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का आग्रह किया है।

इस विवाद की शुरुआत सतना में आयोजित एक युवा संवाद कार्यक्रम से हुई थी। वहां जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को मोहन लाल अभिनंदन यादव कहकर संबोधित किया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था, हां हम तो अभिनंदन लाल हैं, तुम टपोरी लाल हो।

> **यह रहे उपस्थित**
>
> ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिलदार सोलंकी, प्रशांत सेन, प्रिंस शर्मा, इकबाल शाह, उषा सैनी, विमल सोलंकी, कमल चौहान और प्रताप सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विधायक ने निरीक्षण कर जताई नाराजगी

निवाली, (नवभारत)। विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम बरडे ने क्षेत्रीय दौरे के दौरान ग्राम वझर पहुंच निर्माणाधीन विद्युत ग्रीड के कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी कमियां पर विधायक बरडे ने नाराजगी व्यक्त की।

एजेंसी व अधिकारियों को दिए निर्देश

इस दौरान पाया कि निर्माण कार्य में उचित क्योरिंग (पानी तराई) नहीं की जा रही थी तथा उपयोग की जा रही रेत एवं सीमेंट की गुणवत्ता भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। इस पर विधायक बरडे ने संबंधित निर्माण एजेंसी एवं अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत ग्रीड का निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार किया जाए। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने व्यक्त की प्रसन्नता

ग्रामीणों ने बताया कि विधायक बरडे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सदैव सजग रहते हैं तथा जनता की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हैं। विधायक द्वारा मौके पर ही निर्देशित किए जाने से ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त की।

विधायक श्याम बरडे ने कहा कि विद्युत ग्रीड के निर्माण से क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा ग्रामीणों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान जनपद पंचायत निवाली अध्यक्ष प्रतिनिधि चतर सिंह पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष जानी, भगवान भाई, प्रकाश जोशी, सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

एक नजर में

अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

आलीराजपुर। कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देशन पर जिले में अवैध रेत खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। प्रभारी खनिज अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री तपीस पांडे द्वारा जानकारी दी गई कि मुखबिरों से प्राप्त सूचना पर 1 जून 2026 को शाम लगभग 5 बजे नायब तहसीलदार सुश्री सरिता बालेचा, नगर सैनिक एवं खनिज विभाग की टीम द्वारा ग्राम साजनपुर स्थित नदी क्षेत्र में संयुक्त जांच की गई। जांच के दौरान नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन करते हुए कई डंपर पाए गए। संयुक्त प्रशासनिक दल को देखकर अधिकांश वाहन चालक अपने डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गए। टीम द्वारा वाहनों की वीडियोग्राफी कर उनके नंबरों का सत्यापन किया गया तथा संबंधित वाहनों की पहचान की गई। कार्रवाई के दौरान जिन वाहनों को अवैध रेत परिवहन में संलिप्त पाया गया, उनमें गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान पंजीयन के कई डंपर शामिल हैं। कुछ वाहन बिना नंबर प्लेट के भी पाए गए। खनिज विभाग द्वारा इन सभी वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की अनुशंसा संबंधित परिवहन विभाग को की गई।

कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने का किया अनुरोध

आलीराजपुर। कलेक्टर नीतू माथुर ने जिले के नागरिकों से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में अपने सुझाव एवं विचार साझा करने की अपील की है।उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयों के अध्ययन और परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।उन्होंने बताया कि समिति द्वारा व्यापक जन-परामर्श के माध्यम से नागरिकों की राय प्राप्त की जा रही है, ताकि विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों पर आमजन के विचारों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जा सके। उन्होंने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि वे अपने सुझाव एवं विचार मध्य प्रदेश शासन की निर्धारित वेबसाइट ह्वष्.द्वश्च.द्दश1.द्ब्ल पर ऑनलाइन प्रेषित करें।नागरिकों की सहभागिता से प्राप्त सुझाव समिति के अध्ययन एवं अनुशंसाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगे,इसलिए अधिक से अधिक नागरिक इस पहल में भाग लेकर अपने सुझाव अवश्य दर्ज कराएं।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं

आलीराजपुर। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। जनसुनवाई कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर नीतू माथुर ने आमजन की शिकायतें सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 35 आवेदन प्राप्त हुए।

इस जनसुनवाई में रेशू मावडा ग्राम बड़ी फोटा तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर ने दिव्यांग पेंशन पुनः प्रारंभ कराने के संबंध में आवेदन देकर बताया कि मैं पैर से दिव्यांग हूं,मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी है। मुझे पूर्व में प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन मिलती थी, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से पेंशन मिलना बंद हो गई है। इस संबंध में उसने कई बार ग्राम सचिव से संपर्क किया, लेकिन आज दिनांक तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं बेरोजगार हूं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हुं। आय का कोई स्थायी स्त्रोत नहीं होने से मुझे जीवन-यापन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पात्रता अनुसार दिव्यांग पेंशन का लाभ पुनः दिलावाया जाए। कलेक्टर श्रीमती माथुर ने सामाजिक न्याय विभाग को प्रकरण की जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार एक अन्य आवेदक नरसिंह भूरिया निवासी ग्राम पनवानी पटेल फलिया ने वर्ष 2006-07 में गिरवी रखे गए चांदी के आभूषण वापस दिलाने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा साहुकार से 35 हजार रुपये उधार लिए गये थे, जिसके बदले लगभग 5 किलोग्राम चांदी के आभूषण गिरवी रखे गए थे। मैं कई बार अपनी चांदी छुड़ाने के लिए साहुकार के पास गया, लेकिन उसने न तो आभूषण वापस दिए और न ही ब्याज सहित देय राशि की स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने आवेदन देकर कहा कि मेरे गिरवी रखे गए चांदी के आभूषण वापस दिलवाए जाए। उक्त आवेदन को कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, हैंडपंप खनन एवं पुलिया निर्माण जैसी समस्याओं से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए। इस दौरान जनसुनवाई कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संघमित्रा गौतम,एडीएम सोहन कनाश, डिप्टी कलेक्टर सुश्री निर्मला कलमें सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई का सकारात्मक परिणाम, कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल छात्रा को मिला शिक्षा ऋण

आलीराजपुर । पूर्व जनसुनवाई में प्रस्तुत एक शिक्षा ऋण संबंधी समस्या का त्वरित समाधान करते हुए कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देश पर मेडिकल छात्रा सुश्री अर्चना चौहान को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

आलीराजपुर जिले के विकासखंड सोंडवा के ग्राम खामट की निवासी सुश्री अर्चना चौहान ने जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर को आवेदन देकर बताया था कि वह मानसरोवर मेडिकल कॉलेज, सीहोर में प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। उनके पिता किसान हैं तथा परिवार में तीन भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च वहन करना आर्थिक रूप से कठिन हो रहा है। ऐसे में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें शिक्षा ऋण की आवश्यकता थी। सुश्री अर्चना ने बताया कि उन्होंने अपने निवास के निकट स्थित भारतीय स्टेट बैंक, आलीराजपुर शाखा में विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया था, लेकिन ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया लंबित थी। कलेक्टर नीतू माथुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल एलडीएम श्री श्याम पाटीदार को आवेदन का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

एलडीएम श्याम पाटीदार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में सुश्री अर्चना चौहान के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से शिक्षा ऋण की प्रक्रिया प्रारंभ करा दी है।

समस्या के समाधान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुश्री अर्चना चौहान ने कलेक्टर नीतू माथुर का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के हस्तक्षेप और सहयोग से उनकी शिक्षा संबंधी समस्या का समाधान हो गया है तथा अब उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

एक नजर में — कार्यशाला में बताया कि स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाए थीम के तहत जिले की 49 ग्राम पंचायतों से अभियान की शुरूआत की जाएगी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला

आलीराजपुर। जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्ययोजना निर्माण एवं स्वच्छता गतिविधियों के सफल संचालन के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया।

कार्यशाला में स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघमित्रा गौतम ने दिए ।

बैठक में बताया गया कि 'स्वच्छता अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं' थीम के तहत जिले की 49 ग्राम पंचायतों से अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था विकसित की जाएगी। पंचायत स्तर पर घरों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य स्थानों से कचरा एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यशाला में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की जाए। घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए गीले एवं सूखे कचरे का पृथक संग्रहण किया जाए। पंचायतों में निर्धारित स्थानों पर कचरा संग्रहण केंद्र विकसित किए जाएं तथा जैविक कचरे से कम्पोस्ट खाद तैयार करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। प्लास्टिक एवं अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग कर उनके सुरक्षित निस्तारण एवं पुनर्चक्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, स्कूलों एवं शासकीय कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। खुले में कचरा फेंकने, कचरा जलाने तथा नालियों में अपशिष्ट डालने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। स्वच्छता दीदियों, स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम स्तरीय समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर ग्रामीणों को कचरा पृथक्करण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।

कार्यशाला में पॉलीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने पर विशेष चर्चा की गई। बताया गया कि ग्राम पंचायतों को इस संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा उन्हें आवश्यक अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे सरपंच एवं पंचायतें अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकें। पंचायतों को पॉलीथिन जब्ती, जनजागरूकता अभियान एवं उसके सुरक्षित नष्टीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ग्रामों के निर्माण के लिए पॉलीथिन मुक्त पंचायतों का लक्ष्य निर्धारित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पंचायतों में नियमित निगरानी एवं समीक्षा की व्यवस्था विकसित की जाए तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार अपनाने एवं सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संघमित्रा गौतम, संयुक्त कलेक्टर श्री मनोज गरवाल, जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यगण सहित नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने जिले को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।